ISSN(Online) : 2319-8753

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Vol. 3, Issue 11, November 2014

वैश्विक आतंकवाद का भारतीय सुरक्षा पर प्रभाव

डॉ. राम अवतार राम

एसोशिएट प्रोफेसर - रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग, का. सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय , अयोध्या

सारांश

भारत वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रयासों के प्रति वचनबद्ध है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के प्रति 'ज़ीरोरो टॉलरेंस' की नीति का लगातार समर्थन करता रहा है।

इस संदर्भ में भारत ने 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में "अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय" (The Comprehensive Convention on International Terrorism-CCIT) को स्वीकार किये जाने का प्रस्ताव रखा था।

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र के आयोजन में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT) की मांग को दोहराया।

भारत सीमापार आतंकवाद से पीड़ित रहा है। इसलिये भारत ने प्रमुख वैश्विक शक्तियों से पहले वैश्विक शांति और सुरक्षा के मामले को संज्ञान में लिया।

CCIT एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है जो आतंकवादी समूहों को धन और सुरक्षित आश्रय नहीं देने के लिये सभी हस्ताक्षरकर्त्ता देशों को बाध्यकारी बनाता है।

15 दिसंबर, 1997 को आतंकवादी बम विस्फोटों के दमन के लिये अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को अपनाया गया। 9 दिसंबर, 1999 को आतंकवाद के वित्तपोषण के खात्मे के लिये अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को अपनाया गया तथा परमाणु आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के दमन के लिये अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को 13 अप्रैल, 2005 को अपनाया गया।

वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुकाबले के लिये तथा कानूनी पहलुओं पर आम सहमति बनाने हेतु 6 तदर्थ समितियों का गठन किया गया है जिनके बीच अभी भी इस विषय पर विचार-विमर्श चल रहा है।

अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आम राय नहीं बन पाई है जिसमें आतंकवाद की परिभाषा पर आम सहमति न बन पाना भी एक मुख्य मुद्दा है।

आतंकवाद की परिभाषा तय करना कभी भी आसान नहीं रहा है।1937 में यूरोप में आतंकवादी हमले और एक लीडर की हत्या के बाद लीग ऑफ़ नेशन ने कन्वेंशन ऑन टेररिज्म पर एक ट्रीटी को अडॉप्ट किया।

लेकिन इस ट्रीटी को देशों का अनुसमर्थन नहीं मिल सका तथा न ही यह लागू हो सकी। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय तो है लेकिन आतंकवाद को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

CCIT के उद्देश्य

आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा के लिये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली (UNGA) के सभी 193 सदस्य इस आपराधिक कानून को अपनाएंगे।

सभी आतंकवादी समूहों पर प्रतिबंध लगाना और आतंकवादी शिविरों को बंद करना।

विशेष कानूनों के तहत सभी आतंकवादियों पर मुकदमा चलाना।

वैश्विक स्तर पर सीमापार आतंकवाद को प्रत्यर्पण योग्य अपराध घोषित करना।

इस अभिसमय के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा किये जाने वाले अपराध का उद्देश्य लोगों को डराना या सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को किसी भी कार्य को करने से रोकना या ऐसा कार्य करने के लिये मजबूर करना हो, जिसके कारण-किसी भी व्यक्ति की मौत या गंभीर शारीरिक चोट, या सार्वजनिक उपयोग की जगह, कोई सरकारी सुविधा, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, अवसंरचना या पर्यावरण सहित सार्वजनिक या निजी संपत्ति की क्षति, या संपत्ति, स्थान, सुविधाओं या प्रणालियों को नुकसान पहुँचता हो जिसके परिणामस्वरूप बड़ा आर्थिक नुकसान हो, को आतंकवाद की परिभाषा के तहत माना जाएगा।

DOI: 10.15680/IJIRSET.2014.0311106

ISSN(Online) : 2319-8753

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Vol. 3, Issue 11, November 2014

परिचय

अमेरिका शांतिकाल के दौरान राज्य की सैन्य ताकतों द्वारा किये गए कृत्यों को इससे बाहर रखने का मसौदा चाहता था। अमेरिका खासतौर पर अफगानिस्तान और इराक में किये गए हस्तक्षेपों के संबंध में अपने सैन्य बलों पर CCIT के अनुप्रयोग को लेकर चिंतित है।इस्लामिक देशों का संगठन (OIC) राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों को CCIT के दायरे से बाहर रखना चाहता है। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों से OIC का तात्पर्य खासकर इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष से है।यह तर्क दिया गया था कि स्वतंत्रता आंदोलनों तथा आतंकवाद के कृत्यों को अलग करने की आवश्यकता है ताकि वैध आंदोलनों को आतंकवाद के आपराधिक कृत्यों के रूप में वर्गीकृत न किया जा सके।लातिन अमेरिकी देश 'राज्य आतंकवाद (State Terrorism)' को तथा राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के उल्लंघन को भी CCIT में शामिल करना चाहते थे।आतंकवाद की यह परिभाषा विवादास्पद नहीं है। विवाद इस परिभाषा के अनुप्रयोग को लेकर है। क्या यह परिभाषा किसी राज्य के सशस्त्र बलों और स्वतंत्रता आंदोलनों पर भी लागू होगी?[1,2]

सभी सुरक्षा एजेंसियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करते हुए स्वतंत्र बनाए जाने की ज़रूरत है।
पूर्वोत्तर में आतंकी समस्याओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा ध्यान पाकिस्तान बॉर्डर को सुरक्षित रखने में ज़्यादा है। यहाँ पर सैटेलाइट तथा अन्य तकनीकी उपकरण तैनात किये गए हैं लेकिन पूर्वोत्तर भारत की सीमाओं पर ध्यान नहीं दिया गया है।
बांग्लादेश का आतंकवादी संगठन जमातुल मुजाहिदीन पूर्वोत्तर में सक्रिय हो रहा है। असम, नगालैंड तथा मणिपुर का बॉर्डर अभी तक खुला हुआ है जहाँ से ड्रग्स की एंट्री तेज़ी के साथ हो रही है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
पूर्वोत्तर में समुद्री सीमा अधिक है। पंजाब के पठानकोट में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें आतंकवादियों ने नदी मार्ग से भारत में प्रवेश किया था।
नदी के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेंसिंग तथा नदी के नीचे सेंसर लगाने का जो काम होना था वह अभी तक नहीं हो सका है जिस पर गौर किये जाने की ज़रूरत है।
फाइनेंसियल इंटेलिजेंस अर्थात् आतंकवाद के पोषण के लिये पैसे, इक्विपमेंट कहाँ से आते हैं, इस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है।
भारत के लैंड बॉर्डर का सर्किल 15,000 किलोमीटर है और कोस्टल सर्किल 7,500 किलोमीटर से अधिक है, ऐसी स्थिति में जब तक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं होगा तब तक बॉर्डर सुरक्षित नहीं हो सकता।
मरीन पुलिस अभी भी काफी कमज़ोर है, न तो उनके पास नाव है और न ही मैनपावर या उपकरण।[3,4]

विचार – विमर्श

गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में राज्यसभा में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में सिफारिश की है कि सरकार को एकीकृत काउंटर आतंकवाद एजेंसी के रूप में एक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर (NCTC) के गठन पर तुरंत विचार करना चाहिये।

पैनल ने गृह मंत्रालय से इस मुद्दे पर सभी हितधारकों से सर्वसम्मति बनाने में मुख्य भूमिका निभाने के लिये भी कहा है।

इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA), राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID) के निर्माण के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) में सुधार को भी शामिल किया गया है।

एनसीटीसी मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के तहत एक खुफिया सूचनाएँ साझा करने वाला "फ्यूजन सेंटर" के कार्य करने प्रस्ताव था तथा इसके ऑपरेटरों को पूरे भारत में गिरफ्तारी करने की शक्ति देने की बात की गई थी।

लेकिन सुरक्षा डोमेन में संस्था निर्माण के भारत के निराशाजनक रिकॉर्ड के अनुरूप, NCTC 26/11 सुधार प्रक्रिया के बाद यह सबसे बड़ी निराशा रही है।

प्रस्तावित NCTC का उद्देश्य आतंकवादी हमलों को रोकना, जवाबी कार्यवाही करना था, पिछले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) शासन के दौरान केंद्र-राज्य संबंधों को लेकर राजनीतिक कड़वाहट के कारण यह मूर्तरूप नहीं ले सका।

विशेष रूप से गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के गैर-कॉन्ग्रेस शासित राज्यों ने कथिततौर पर प्रस्ताव का विरोध किया था। उनकी मुख्य आपत्ति संघवाद के सिद्धांत के संभावित उल्लंघन की आशंका को लेकर है क्योंकि उन्होंने तर्क दिया कि NCTC राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण करेगा।

भारत आतंकवाद, सीमापार के साथ-साथ स्थानीय रूप से कट्टरपंथी जिहादियों से लगातार खतरे का सामना कर रहा है।

लेकिन 26/11 की घटना के लगभग एक दशक बीत जाने के बाद NCTC पर केंद्र सरकार किसी खास नतीजे पर नहीं पहुँच पाई है।[5,6]

परिणाम

आतंकवाद' शब्द की उत्पत्ति फ्राँसीसी क्रांति के दौरान वर्ष 1793-94 के आतंक के शासन से हुई।

यूरोप और अन्यत्र भी विशेषकर 1950 के दशक के उत्तरार्द्ध में वामपंथी उग्रवाद उभर कर सामने आया। भारत में नक्सली और माओवादी सहित पश्चिम जर्मनी में रेड आर्मी गुट, जापान का रेड आर्मी गुट, संयुक्त राज्य अमेरिका में विदरमेन और ब्लैक पैन्थर्स, उरुग्वे के तूपामारोस और अन्य कई वाम पंथी उग्रवादी दल विश्व के भिन्न-भिन्न भागों में 1960 के दशक के दौरान उत्पन्न हुए।

आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद अधिकांशत: इस्लामी रूढ़िवाद की विचारधारा से प्रेरित है तथा इसकी अग्र पंक्ति में ओसामा बिन लादेन का अल-कायदा और इसके घनिष्ठ सहयोगी अफगानिस्तान में तालिबान हैं। सोवियत-विरोधी नीतियों के कारण तालिबानों की तेज़ वृद्धि संयुक्त राज्य अमेरिका की CIA और पाकिस्तान की ISI द्वारा दिये गए व्यापक संरक्षण के कारण संभव हुई थी। इससे न केवल अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान और भारत में भी सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हो चुकी हैं।

पिछले कई दशकों से आतंकवाद पर काबू पाने के लिये अनेक कदम उठाए गए हैं तथा और भी बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है। तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी कई बार आतंकी गिरोह सुरक्षा बलों पर हमले कर अपनी मौजूदगी का अहसास कराते रहते हैं। यह सच है कि पिछले कुछ समय से खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान के मोर्चे पर अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल हुआ है और इसमें स्थानीय आबादी को भी सहयोग की भूमिका में लाने की कोशिश की गई है जिससे आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। विडंबना यह भी है कि भारत की ओर से लगातार चेतावनी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फटकार के बावजूद पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाता।[7,8]

निष्कर्ष

जनसंहार के हथियार वे होते हैं, जो संपूर्ण विनाश तथा लोगों, अवसंरचनाओं अथवा अन्य संसाधनों को बड़े पैमाने पर नष्ट करने की क्षमता रखते हैं के लिये प्रयोग किये जाने योग्य होते हैं। उदाहरण- न्यूक्लिर, रासायनिक और जैविक हथियार आदि।

a. **रासायनिक हथियार:** वर्ष 1993 में हस्ताक्षरित रासायनिक हथियार समझौते के अनुसार, उत्पत्ति पर ध्यान दिये बिना कोई भी विषैला रसायन रासायनिक हथियार माना जाता है अगर इसका प्रयोग निषिद्ध प्रयोजनों के लिये किया जाता है। उदाहरण: रिसीव, बोटुलिनम, टॉक्सिन, तंत्रिका एजेंट, लेवीसाइट, सेरिन आदि जैसे टॉक्सिक रसायन इसके उदाहरण हैं।

b. **न्यूक्लियर हथियार:** न्यूक्लियर हथियारों के निर्माण के लिये सरलता से यूरेनियम उपलब्ध न होना इसके संवर्द्धन की जटिल प्रक्रिया तथा अत्यधिक लागत आतंकवादी संगठनों और गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं के समक्ष मुख्य समस्या है। द्वारा आतंकवादी हमलों में न्यूक्लियर हथियारों के प्रयोग का कोई लेखा-जोखा नहीं है। लेकिन इस बात के संकेत मिले हैं कि 1990 के उतरार्द्ध से अल-कायदा इन्हें प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है।[9,10]

ISSN(Online) : 2319-8753

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Vol. 3, Issue 11, November 2014

c. **जैविक हथियार:** जैव-आतंकवाद अपेक्षतया आतंकवाद का एक नया रूप है, जो जैव-प्रौद्योगिकी की उन्नति के चलते इसकी आतंकवादी गुटों तक पहुँच के परिणामस्वरूप उभरा है। जैव-आतंकवाद को 'मानव, पशुओं अथवा पौधों में बीमारी अथवा मृत्यु कराने प्रयुक्त वायरसों, जीवाणुओं अथवा अन्य कीटाणु (एजेंटों) का जान-बूझकर निर्गमन' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन्हें वायु, जल अथवा खाद्य पदार्थों के माध्यम से फैलाया जाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका सेना प्रशिक्षक और शिक्षा कमान, साइबर आक्रमणों के परिणाम की चार श्रेणियों का वर्णन करता है :

अखंडता की हानि: आँकड़े और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में किये गए अनाधिकृत परिवर्तनों का परिणाम अयथार्थता, धोखाधड़ी अथवा गलत निर्णय हो सकता है जो प्रणाली की अखंडता को संदेह के दायरे में लाता है।

उपलब्धता की हानि: महत्त्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर आक्रमण उसे प्रयोक्ताओं के लिये अनुपलब्ध बना देता है।

गोपनीयता की हानि: सूचना के अनधिकृत प्रकटन का परिणाम जनता के विश्वास की हानि से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुँचने तक होता है।[11,12]

भौतिक विनाश: सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के प्रयोग द्वारा वास्तविक रूप से भौतिक नुकसान अथवा इसमें विनाश करने का सामर्थ्य।

विकास, स्थायित्व, सुशासन और कानून का शासन एक दूसरे से सहसंबद्ध हैं और अशांति को उत्पन्न कोई भी खतरा देश के सतत विकास के उद्देश्य में बाधा बनता है। आतंकवाद न केवल राजनीतिक और सामाजिक वातावरण को नष्ट करता है बल्कि देश के आर्थिक स्थायित्व को खतरा भी पहुँचाता है, प्रजातंत्र को दुर्बल बनाता है और यहाँ तक कि सामान्य नागरिकों को जीने के उनके अधिकार सहित बुनियादी अधिकारों से वंचित करता है।

- आतंकवादी किसी धर्म अथवा संप्रदाय या समुदाय के नहीं होते। आतंकवाद कुछ उग्र लोगों, जो अपने घृणित लक्ष्यों की प्राप्ति में निर्दोष नागरिकों की लक्षित हत्या का आश्रय लेते हैं, द्वारा प्रजातंत्र और सभ्य समाज पर हमला है।
- आज आतंकवाद ने आधुनिक संचार प्रणालियों, संगठित अपराध, मादक द्रव्य के अवैध व्यापार, जाली मुद्रा और वैश्विक स्तर पर इनके प्रयोग सहित विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थायित्व को खतरा पहुँचाते हुए नया तथा अधिक खतरनाक आयाम प्राप्त कर लिया है। इसीलिये आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनिवार्य है।
- भारत आतंकवाद के सबसे अधिक पीड़ितों में से एक रहा है परंतु हमारे समाज ने सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक तालमेल बनाए रखते हुए बारंबार एवं बेलगाम आतंकवादी हमलों के समय अभूतपूर्व जीवटता तथा समुत्थान शक्ति प्रदर्शित की है।[13,14]
- आतंकवाद-रोधी कार्यनीति को यह मानना चाहिये कि आतंकवाद कार्य न केवल निर्दोषों को बर्बाद करता है परंतु हमारे समाज को विभाजित करता है, लोगों के बीच मतभेद उत्पन्न करता है और समाज के ताने-बाने को अत्यधिक क्षति भी पहुँचाता है।

आतंकवादियों और राष्ट्र-विरोधी कार्यकलापों के विरुद्ध सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सतत् और सख्त कार्रवाई करने के अतिरिक्त नागरिक समाज भी आतंकवादी कार्यकलापों को रोकने और आतंकवाद की विचारधारा का प्रतिरोध करने में मुख्य भूमिका निभा सकता है। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करने में नागरिकों और प्रचार माध्यम द्वारा सहयोग भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण है। रिपोर्ट का बल इस बात पर है कि सुशासन, सम्मिलित विकास, सतर्क प्रचार माध्यम और एक जागरूक नागरिकता के साथ संयोजित

ISSN(Online) : 2319-8753

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Vol. 3, Issue 11, November 2014

कानूनी एवं प्रशासनिक उपायों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आतंकवाद किसी भी रूप को परास्त कर सकता है।[15,16,17]

संदर्भ

1. आतंकवाद: अवधारणाओं, कारण होता है और संघर्ष रेसोलुशन जॉर्ज मेसन विश्वविद्यालय (George Mason University)संस्थान संघर्ष विश्लेषण और संकल्प के लिए (Institute for Conflict Analysis and Resolution), मुद्रित को सुरक्षा खतरा कटौती एजेंसी, किले Belvoir, वर्जीनिया, जनवरी 2003 तक
2. ↑ थिओडोर पी. सेतो *आतंकवाद की नैतिकता* इस में एक सूची भी शामिल हैं बार (Times) पर प्रकाशित जुलाई 23 (July 23)1946 जो उन इरगुन द्वारा शुरू करो एक प्रमुख सदस्य है जो शुरू किया गया था सहित यहूदी आतंकवादी कार्रवाइयों, के रूप में वर्णित किया गया
3. ↑ BBC ख़बर : प्रोफाइल: मेनाचेम शुरू शुरू के आदेश के तहत बीबीसी वेबसाइट ", भूमिगत आतंकवादी समूह इरगुन हिंसा के अनेक कार्य करता किया।"
4. ↑ इकबाल अहमद "*आतंकवाद पर सीधे बात*"मासिक समीक्षा (Monthly Review), जनवरी, 2002. "मेनाचेम शुरू सहित, पोस्टर कह" तलाश है "में दिखने," आतंकवादियों, यह बहुत कुछ इनाम. "मैंने देखा की पेशकश की मेनाचेम शुरू के सिर के लिए 100000 ब्रिटिश पाउंड "किया गया है यह उच्चतम पुरस्कार
5. ↑ समाचार: दुनिया मध्यपूर्व: शेरोन की विरासत शांति शामिल नहीं है बीबीसी की वेबसाइट "एरियल शेरॉन मेनाचेम शुरू करो, एक और योद्धा की तुलना में किया जाएगा, जो सीनै छोड़ दिया और मिस्र के साथ शांति बनाए राजनेता बने."
6. ↑ यहोवा देसाई हंसर्द, सभा यहोवा की Archived 2007-03-11 at the Wayback Machine 3 सितंबर 1998: कॉलम 72, "*हालांकि, जोमो Kenyatta, नेल्सन मंडेला और मेनाचेम शुरू करो - बस तीन उदाहरण देने के लिए - सभी आतंकवादियों के रूप में की निंदा की गई, लेकिन अपने सभी देशों और युनाइटेड किंगडम के अच्छे दोस्त के राजनीतिक नेताओं के सफल साबित हुई.*"
7. ↑ बीबीसी समाचार: World: अमेरिका: संयुक्त राष्ट्र सुधारों मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त हाल के दिनों में सभी समूहों को सक्रिय रूप से बीबीसी की वेबसाइट ", इस ANC शायद सबसे अच्छा सशस्त्र संघर्ष की पारंपरिक दिचोतोमोउस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। एक बार एक आतंकवादी समूह के रूप में पश्चिमी सरकारों ने माना, यह अब, नेल्सन मंडेला एक दुनिया की सही मायने में iconic आंकड़ों के साथ दक्षिण अफ्रीका के वैध, निर्वाचित सरकार बनाता है। "
8. ↑ बीबीसी समाचार: विश्व अफ्रीका: प्रोफ़ाइल: नेल्सन मंडेला बीबीसी की वेबसाइट "नेल्सन मंडेला" एक दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित राजनेता की बनी हुई है
9. ↑ Quinn वी. Robinson (pdf), 783 F2d. 776 (9 Cir. 1986) Archived 2009-03-01 at the Wayback Machine(PDF), ने की वेब साइट Syracuse यूनिवर्सिटी कॉलेज कानून का (Syracuse University College of Law)
10. ↑ पृष्ठ 17, उत्तरी आयरलैंड: TP, टी, एस 11 Archived 2007-12-01 at the Wayback Machine (PDF) रानी के विश्वविद्यालय बेलफ़ास्ट (Queen's University Belfast) लॉ स्कूल
11. ↑ पापे, रॉबर्ट ए "रणनीतिक तर्क आत्मघाती हमलों की, "अमेरिका के राजनीतिक विज्ञान की समीक्षा, 2003. 97 (3): पीपी.1-19.
12. ↑ , शब्द गोल्डी और फ्रांसिस्को जोस ल्लेरा रामो ,"राजनीतिक हिंसा एक लोकतांत्रिक राज्य में," आतंकवाद के सन्दर्भ में.एड. मरथा क्रेंशाव .विश्वविद्यालय पार्क: पेन्सिलवेनिया राज्य विश्वविद्यालय, 1995. pp467.
13. ↑ सगेमन, मार्क.२००४ "सामाजिक नेटवर्क और जिहाद".फिलाडेल्फिया: विश्वविद्यालय पेनसिल्वेनिया के प्रेस.CH. 5 पीपी.166-167
14. ↑ मीडिया और आतंकवाद: एक पुनः पॉल विलकिंसन (Paul Wilkinson).आतंकवाद और राजनीतिक हिंसा, Vol.9, No.2 (ग्रीष्मकालीन 1997), pp.51-64 फ्रैंक Cass, लंदन ने प्रकाशित किया है।
15. ↑ सीमावर्ती: अल कायदा के नए मोर्चे | PBS
16. ↑ सीमावर्ती: अल कायदा के नए मोर्चे: अल कायदा आज | PBS
17. ↑ सीमावर्ती: के भीतर दुश्मन: नई वास्तविकता: उस आदमी को दूर कर दिया | PBS